नगर निगम के जेई को अतिक्रमण में दिखीं सिर्फ तीन दुकानें

कौशल रोजगार के जेई ने अधिकार क्षेत्र के बाहर हूडा के सेक्टर में की तोड़फोड़

जनता के दबाव में चला अभियान, नेता के दबाव में छोड़ दीं बाकी दुकानें

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) राजनेताओं का चरणवंदन कर लूट कमाई में मस्त प्रशासनिक अधिकारियों को आम जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई मुद्दा उठा तो कार्रवाई का नाटक किया जाएगा। कार्रवाई भी उन लोगों पर की जाती है जो या तो राजनीतिक विरोधी हों या फिर आकाओं को सुविधा शुल्क नहीं चुका रहे हैं। गड़बड़ी होने पर अपना अधिकार क्षेत्र न होने की बात कह कर पल्ला झाड़ने वाले नगर निगम अधिकारी काली कमाई का जुगाड़ देखते ही कहीं भी कार्रवाई करने को बेताब हो जाते हैं। नगर निगम में कौशल रोजगार के तहत कार्यरत ऐसे ही जेई ने अपने राजनीतिक आका को खुश करने के लिए हूडा के सेक्टर 21सी में तोड़फोड़ कर डाली लेकिन केवल तीन दुकानें तोड़ कर लौट आया क्योंकि ये दुकानदार आका को पैसा नहीं देते थे।

सेक्टर 21 सी की विधायक सीमा त्रिखा द्वारा पोषित आरडब्ल्यूए का कारोबार महेंद्र शर्मा संभालते हैं। कहा जाता है कि सीमा त्रिखा ने ही उन्हें अपने राजनीतिक प्रभाव से आरडब्ल्यूए और कम्युनिटी सेंटर की चौधर

सीमा की छत्रछाया में पलता महेंद्र शर्मा

दिलाई। इस सेक्टर में पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने वाली पट्टी से लेकर हूडा मार्केट के आसपास तक अवैध रूप से अस्थायी दुकानें व रेहड़ियां लगाई जाती हैं। यही नहीं हूडा मार्केट के सामने खाली पड़ी हूडा की जमीन में चारदीवारी गिरा कर यहां अवैध सब्जी मंडी बसा दी गई है। इलाके में रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सब्जी मंडी में दुकान लगाने का एक हजार रुपये महीना और सड़क पर लगाने का पचास से सौ रुपये प्रति दिन प्रति रेहड़ी आरडब्ल्यूए के चौधरी महेंद्र शर्मा के गुर्गे वसूलते हैं। शाम को बल्ब जलाने के लिए पचास रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वसूली भी वही करते हैं। इसके बदले प्रशासन द्वारा दुकानें नहीं हटाए जाने का अभयदान मिला हुआ है।

एक जून की शाम एक जोड़ा सेक्टर 21सी के कम्युनिटी हॉल के पीछे आपत्तिजनक हालत में नशा करते हुए देखा गया। सेक्टर के कुछ युवकों ने विरोध किया तो बात बढ़ गई। पुलिस भी आ गई, सब को दो जून की शाम पांच बजे अनखीर चौकी पर बुलाया गया। दो जून को वहां सेक्टर के ढेर सारे महिला-पुरुष पहुंच गए। सबने एक सुर में सेक्टर में अवैध कब्जा, अतिक्रमण, सड़कों तक रेहड़ी लगाए जाने के कारण जाम और वाहन पार्किंग की समस्या उठाई। महेंद्र शर्मा के गुर्गों ने बात अराजक तत्वों की तरफ मोड़ने का भरसक प्रयास किया लेकिन लोग इन्हीं समस्याओं का समाधान कराने की बात पर अड़े रहे। आखिर में पुलिस अधिकारियों ने अवैध दुकानदारों और रेहड़ी वालों को नहर पार भिजवाने का आश्वासन दिया तब लोग माने।

मालूम हो कि इस सेक्टर में अतिक्रमण या अवैध कब्जे के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई हूडा का अधिकार क्षेत्र है। बावजूद इसके तीन जून को नगर निगम के कौशल विकास का जेई प्रवीण बैंसला तोड़फोड़ दस्ता लेकर पहुंचा। कार्रवाई न होने का अभयदान पाए दुकानदारों को छोड़ते हुए उन्होंने हूडा मार्केट के बाहर अस्थायी रूप से बनीं तीन दुकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई कर दी।

इस दौरान राजनीतिक आका ने काम समाप्त करने का इशारा किया तो जेई ने कार्रवाई रोक दी। लोगों ने बाकी दुकानें भी तोड़ने को कहा तो जेई ने कहा कि उनके लिए जब आदेश आएगा तब उन्हें तोड़ेंगे। गुस्साए लोगों ने उनसे पूछा कि किस अधिकार से हूडा के सेक्टर में अधूरी तोड़फोड़ की तो वह बिना जवाब दिए चलते बने। लोगों में चर्चा रही कि महेंद्र शर्मा ने केवल वे दुकानें तुड़वाईं जो पैसा नहीं देते थे और उनको बचा लिया जो पैसा देते हैं।

बताते चलें कि इस सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर का अलॉटमेंट हूडा ने असली एवं निर्वाचित आरडब्ल्यूए को किया था। इसके अध्यक्ष जगदीश चौहान हैं। 2017 में हूडा का यह सेक्टर नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था। 2018 में सीमा त्रिखा के दबाव में तत्कालीन निगमायुक्त ने इस कम्युनिटी सेंटर को महेंद्र शर्मा के हवाले कर दिया। और तो और सरकारी गुंडागर्दी की इंतेहा तो तब हो गई जब महेंद्र शर्मा को कब्जा देने के लिए निगम वालों ने जगदीश चौहान वाली एसोसिएशन का ताला तोड़कर वहां रखे सामान को बाहर फिकवा दिया था।

रेलवे द्वारा 288 लोगों की हत्या, जिम्मेदार कोई नहीं, सीबीआई तलाशेगी बलि का बकरा

सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर मौत को न्यौता जाये तो हत्याकांड ही बनेगा

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

ओड़िसा के बालासोर में शुक्रवार दो जून को तीन ट्रेनों की भिड़ंत में 288 बेगुनाह यात्री मारे गये तथा 1000 घायल हुए। भारतीय रेलवे द्वारा किये जाने वाले इस तरह के हर हत्याकांड के लिये एक जांच बैठाने का नाटक किया जाता है। जांच रिपोर्ट न तो कभी प्रकाशित होती है और न ही भविष्य में होने वाले इस तरह के हत्याकांडों को रोकने के लिये कोई कदम उठाये जाते हैं।

इस जघन्य हत्याकांड को लेकर भी पहले की तरह जांच की नौटंकी शुरू हो गई है, साथ में किसी सम्प्रदाय विशेष को लपेटने के लिये इसे 'षडयंत्र' का नाम देकर पुलिसिया (सीबीआई) जांच के भी आदेश दे दिये गये हैं। इस हत्याकांड के असल गुनाहगारों को ट्रैक के पास मौजूद एक मस्जिद व शुक्रवार का दिन होना नजर आता है।

घटना का कारण बिल्कुल साफ़ नजर आ रहा है कि हावड़ा से चेन्नई जा रही जिस कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को 128 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से सीधे निकल जाने का सिग्नल दिया गया था, वह सीधे न जाकर लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी पर इसलिये जा चढ़ी कि उसे दिया गया सिग्नल स्वत: हट गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इन्टरलॉकिंग सिग्नल प्रणाली में आई खराबी के कारण ऐसा हुआ। सिग्नल सिस्टम में इस तरह की खामियों के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को पहले भी कई बार बताया जा चुका था। बहुत दिन नहीं हुए जब फरवरी 2023 में दक्षिण-पूर्व रेलवे के मैसूर के पास में सम्पर्क क्रांति ट्रेन सिग्नल फेल हो जाने के कारण दूसरी पटरी की ओर चल दी थी। सतर्क लोको पॉयलट ने जैसे-तैसे हादसा होने से बचा लिया था। मामले की जांच करने पर पाया गया था कि सिग्नल प्रणाली में भारी गड़बड़ है। इस पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने 9 फरवरी को जारी अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि यदि इन खामियों को दूर न किया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और वही हो भी गया क्योंकि रिपोर्ट पर किसी ने

अमल नहीं किया। हिंद मजदूर सभा के महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू ने लिखित बयान में बताया है कि रेलवे में एक वर्ष में सिग्नल फेल होने के 51,238 मामले दर्ज किए गए।

रेलवे में आज के दिन 3 लाख 42 हजार पद खाली पड़े हैं। इनमें से 36,000 सिविल इंजीनियर्स और 34000 मेकेनिकल इंजीनियर्स के ही पद हैं। एक लाख से अधिक वे पद खाली पड़े हैं जो सीधे तौर पर रेल सुरक्षा से सम्बन्धित हैं। लोको पायलटों की बनाई गई कमी के चलते इन्हें 14-16 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है जो बहुत ही खतरनाक है।

जबसे रेलवे बनी है, इसमें रेल सुरक्षा आयुक्त का पद इतना महत्वपूर्ण समझा गया था कि इसे पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की गई थी, अर्थात न तो यह रेलवे बोर्ड के मातहत और न ही रेलवे मंत्रालय के मातहत आता था। इसकी जिम्मेवारी होती है कि वह सारे रेलवे ट्रैक एवं तमाम सम्बन्धित प्रणालियों की लगातार जांच करने के उपरांत ट्रेनों को चलने की अनुमति दे। इस काम के लिए उसके पास लाखों कर्मचारियों का अमला होता है।

किसी भी ट्रैक पर सुरक्षा मानकों में कमी पाये जाने पर ट्रेनों के परिचालन को रोकने का इसे अधिकार होता था। लेकिन मोदी सरकार ने इस आयुक्त की इस शक्ति को समाप्त कर दिया। जाहिर है कि ऐसा करने से तमाम ट्रेनें सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए फर्राटा भरने को मुक्त हो गईं। इसी का परिणाम मौजूदा हत्याकांड है।

इसके अलावा रेलवे पर बनी संसदीय कमेटी, जिसमें भाजपा सांसदो का बहुमत है और उन्हीं का चेयरमैन भी है, द्वारा रेलवे में मौजूद तमाम खामियों का विस्तृत विवरण अपनी रिपोर्ट में कई बार दिया है। कैग द्वारा, गत वर्ष दी गई रिपोर्ट में भी इसी तरह की अनेक गम्भीर एवं खतरनाक खामियों का विवरण दिया गया था। लेकिन अपने आपको सर्वज्ञ मानने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कान पर कभी जूं तक नहीं रेंगी। सर्वविदित है कि इनके मंत्रीमंडल में बैठे तमाम मंत्री केवल नाम के हैं काम तो सारा मोदीजी ने अपने कांधों पर लाद रखा है। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाना तथा आजकल वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना ही वे अपना एक मात्र कर्तव्य समझते हैं।

संदर्भवश नवंबर 2016 में कानपुर (पुखरायां) में हुई ऐसी ही रेल दुर्घटना जिसमें सैकड़ों आदमी मारे गए थे उसमें भी अपनी करतूतों को छिपाने के लिए तथा पाकिस्तान को लपेटने के लिए एनआईए द्वारा पुलिसिया जांच के आदेश दिए गए थे। उसकी आज तक कोई भी जांच रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है और न ही किसी को उसके लिए दोषी ठहरा कर सजा दी गई है।

आमने सामने की टक्कर को बचाने के लिए आज तकनीकी इतनी उन्नत हो चुकी है कि टकराव रोधी प्रणाली एंटी कोलिजन डिवाइस विकसित कर ली गई है। यूं तो यह प्रणाली सन 2009-10 में सामने आ गई थी उस वक्त ममता बनर्जी रेल मंत्री हुआ करती थीं। उसी प्रणाली का नाम मोदी सरकार ने कवच रख दिया और कवच के ऊपर अपनी फोटो लगवा दी। बहुत समय नहीं हुआ जब मौजूदा रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस प्रणाली का प्रदर्शन करते हुए बताया था कि किस प्रकार आमने-सामने की ट्रेन आते हुए भी स्वत: रुक जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद इस प्रणाली को महज इसलिए लागू नहीं किया जा सका कि इस पर 36,000 करोड़ रुपये का खर्च आ रहा था। मोदी के पास बुलेट ट्रेन के लिए तथा वंदे भारत के लिए तो लाखों करोड़ रुपये हो सकते हैं लेकिन आम जनता की सुरक्षा के लिए महज 36000 रुपये नहीं है।

इतनी भयंकर दुर्घटनाओं के समय आरएसएस के लोग सबसे पहले और सबसे बड़ी संख्या में पहुंचा करते थे लेकिन इस बार एक भी निक्कर धारी वहां नहीं पहुंचा। इनके अलावा किसी भी राजनीतिक दल चाहे वह कांग्रेस, सीपीआई किसी के भी आदमी वहां नहीं पहुंचे। बचाव एवं राहत का सारा काम ओडीआरएफ ने बड़ी फुर्ती और गंभीरता से अंजाम दिया। इस घटना को देख कर नब्बे के दशक में ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की याद आ गई जो रात के करीब ढाई बजे हुई थी, एक घंटे के भीतर भीतर सैकड़ों निक्करधारी स्वयं सेवक मौके पर पहुंच कर राहत कार्यों में जुट गए थे, उन्हीं में एक स्वयंसेवक एस्कॉर्ट ट्रैक्टर कंपनी का वर्कर भी था। सहायता कार्य करते समय उन्हें 1.07 लाख रुपयों से भरा लिफाफा मिला था जिसे उन्होंने पुलिस एवं रेलवे अधिकारियों को सौंपा था। संघ की कार्यशैली को देखकर वर्ष 2000 में वे इससे अलग हो गए थे। स्वयंसेवकों की मौजूदा विमुखता के बारे में उनका कहना था कि वह वक्त चला गया जब स्वयं सेवक सेवा करने में विश्वास रखते थे अब तो मेवा खाने की बेला है सब मेवा खाने में जुटे हैं इतनी फुर्सत कहां बची है कि रात दिन मुर्दों और घायलों में अपना समय बर्बाद करें।

किसानों पर लाठीचार्ज सरकार के कफन में आखिरी कील साबित होगी : कांग्रेस

करनाल। शाहबाद में किसानों पर लाठीचार्ज करने की करनाल कांग्रेस कमेटी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण धरने पर बैठे किसानों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया। अन्नदाताओं को सड़कों पर घसीटा गया, सरकार ने एक बार फिर किसान विरोधी कार्रवाई की है। किसानों पर लाठीचार्ज सरकार के कफन में आखिरी कील साबित होगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं करती। मजबूर होकर किसानों को आंदोलन करना पड़ता है। किसान जब अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकार उन्हें लाठी गोली से दबाने का काम करती है। पहले तीन कृषि कानून देश के किसानों पर जबरन थोपे गए थे। बाद में आंदोलन के दबाव में कानून वापस लिए गए। एमएसपी की गारंटी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। सूरजमुखी फसल पर एमएसपी को लेकर किसान संगठनों ने कई बार सरकार से वार्ता की, मगर सरकार ने किसान हित में फैसला नहीं लिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। अन्नदाताओं की आवाज को सरकार लाठी गोली का डर दिखाकर कुचल नहीं सकती।

इस अवसर पर जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह, रघबीर संधु, कृष्ण बसताड़ा, पप्पू लाठर, सतपाल जाणी, रानी कांबोज, गुरविंद्र कौर व सपना राणा ने अपने बयानों में सरकार का जमकर कोसा।